1974 के बिहार छात्र आन्दोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका

डॉ. रंजीत कुमार

+2 सहायक शिक्षक
इंटर स्तरीय विद्यालय सजौर, फतेहपुर, भागलपुर
Email-ranjeetkr1982@gmail.com

सार : मनुष्य और समाज दोनों परस्पर पूरक हैं और छात्र इसका एक अभिन्न अंग हैं। एक के बिना दूसरे का स्थायित्व संभव नहीं है। छात्र शक्ति, समाज को सुधारने और उसे मजबूत करने वाली घटकों में से एक है। इसलिए कहा जाता है की युवा देश के रीढ़ हैं, जिसके कंधे पर देश का भविष्य टिका होता है। स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद भारत में जितने भी परिवर्तनकारी सामाजिक आंदोलन हुए, उनमें छात्रों की भूमिका बहुत अहम रही है। बिहार से प्रारंभ 1974 का छात्र आन्दोलन परिस्थितियों की उपज थी, एक असंगठित शक्ति का ही रूप और परिणाम था। प्रारंभ में बिहार आन्दोलन कोई राजनीतिक आन्दोलन नहीं थी। इस आन्दोलन की शुरूआत संसदीय राजनीति से बाहर हुई थी। बिहार के छात्र आन्दोलन का मकसद समाज और देश में आमूल चूल परिवर्तन से था, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्ठाचार के विरूद्ध था। आन्दोलन से दश को एक सबसे बड़ी चीज यह मिली कि युवा शक्ति केवल सरकार और राजनैतिक दलों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रही बल्कि राजनैतिक दलों से थोड़ा हट कर जनतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष करती रही। वास्तव में इस आन्दोलन की कोई ऐतिहासिक तैयारी नहीं थी लेकिन जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन से जुड़ने के बाद इसका स्वरूप बनने लगा। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में सम्पूर्ण क्रान्ति की घोषणा की जिसके परिणामस्वरूप छात्रों, जनता एवं युवा वर्ग की ओर से भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी एवं कुशिक्षा को प्रश्रय देने वाली सरकार के खिलाफ आन्दोलन का बिगुल फूँका। हर सरकारी कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन, अनशन, सत्याग्रह, मौन जुलूस, चौक चौराहें पर नुक्कड़ सभाएँ इत्यादि आन्दोलन के मुख्य रूप थे। प्रस्तुत लेख में बिहार का छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के महत्व को रेखांकित किया गया है।

शब्द कुंजी : **छात्र आन्दोलन, राजनीतिक आन्दोलन, जयप्रकाश नारायण, आपातकाल, मीसा, संपूर्ण क्रांति।**

प्रारंभ में बिहार आन्दोलन कोई राजनीतिक आन्दोलन नहीं थी। इस आन्दोलन की शुरूआत संसदीय राजनीति से बाहर हुई थी। बिहार के जन आन्दोलन का मकसद था समाज और देश में आमूल चूल परिवर्तन हो– बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार खत्म हो। उस समय कांग्रेस सरकार और इन्दिरा गांधी ने गरीबी और देश, समाज की जटिल समस्याओं को नहीं समझने में नाकाम रही। बिहार के छात्र आन्दोलन से देश को एक सबसे बड़ी चीज यह मिली कि युवा शक्ति केवल सरकार और राजनैतिक दलों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रही बल्कि राजनैतिक दलों से थोड़ा हट कर जनतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष करती रही। वास्तव में पहले आपातकाल का ऐलान करके इन्दिरा गांधी ने राजनीतिक दलों को जा आन्दालन के व्यापक उद्वेश्य के साथ नहीं आ पा रहे थे और जनता सरकार जैसे मौलिक कार्यक्रमों से उदासीन थे, एक नयी हैसियत दे दी। जनसंघ, सोशलिस्ट आदि पार्टियों ने मौके का फायदा उठाकर विद्यार्थियों को जुटा कर गोलमाल मांगों के आधार पर शिक्षा में सुधार, भ्रष्टाचार आदि को सामने लाकर आन्दोलन की शुरूआत की। संयोगव ा की बात थी कि उस समय पूरे देश में खाद्यानों का संकट था जो आन्दोलन का एक प्रमुख मुद्दा बन गया। इसी के तहत विधान सभा भंग करो की मांग शुरू हुई, पूरे देश से सारी राजनैतिक पार्टियों ने पटना में राज्य सरकार से इस्तीफे के लिए दबाब बनाना प्रारंभ किया। कर्पूरी ठाकुर ने अपने कुछ साथियों का इस्तीफा जयप्रकाश नारायण का सौंप दिया। विधायकों को घेर–घेर कर इस्तीफे के लिए बाध्य किया गया जिससे आन्दोलन एक राजनैतिक आन्दोलन में बदल गयी। श्री अब्दुल गफूर खां ने आन्दोलन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हिन्दुस्तान में सबसे पहला गड़बड़ी का दिन था– इलाहाबाद अदालत का इन्दिरा गांधी के चुनाव से सम्बन्धित फैसला, मेरा अपना विचार है कि इन्दिरा गांधी अगर उसी वक्त अपना इस्तीफा दे देती तो दुनिया में उनकी इज्जत भी बढ़ जाती और कांग्रेस का स्थायित्व भी बना रहता।[1] उन्होंने आगे कहा कि अगर आपातकाल स्थिति ही लगानी थी तो 1974 में लगाना चाहिए था जब बिहार में आंदोलन जोरों पर था। बाद में आपात्कालीन स्थिति की घोषणा बिल्कुल गलत थी। प्रारम्भ में आन्दोलन की शुरूआत की वजहें बड़ी साधारण थी। इस आन्दोलन की कोई ऐतिहासिक तैयारी नहीं थी। मगर धीरे–धीरे उसे राजनैतिक स्वरूप देने की कोशिश की गयी और एक स्वरूप बनने लगा। सोशलिस्ट, भालोद दलों के लोगों ने महंगाई, भष्टाचार आदि को हटाने का मुद्दा उठाकर छात्र आन्दोलन को एक व्यापक स्वरूप देने की कोि ा ा जो जन असन्तोष से सम्बन्धित मुद्दे थे। लेकिन फिर भी यह जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन में शामिल होने से पूर्व कोई स्वरूप स्थापित नहीं हो पाया था। क्योंकि आन्दोलन के लिए कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं था जो अखिल भारतीय स्तर का हो। लेकिन जयप्रकाश नारायण के इस आन्दोलन से जुड़ने के बाद इसे एक व्यापक संदर्भ और व्यक्तित्व तथा लोगों का विश्वास मिला। इस आंदोलन में सहयोग देने वाले बेरोजगार, मध्यम वर्गीय तथा कथित बुद्धिवादी व निश्चित आमदनी के शहरी लोग थे जो महंगाई, बेरोजगारी आदि की परेशानियाँ थे। यह आंदोलन वास्तव में शहरी आन्दोलन था, जो धीरे–धीरे राजनैतिक आन्दोलन में बदल गया। ग्रामीण क्षेत्रों से इसे कोई उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। जयप्रकाश नारायण की प्रमुख हिस्सेदारी के बाद भी यह मध्यम वर्ग का शहरी आन्दोलन ही रहा। इसका एक कारण यह था कि आन्दोलन के नेतृत्वकर्त्ता ने ग्रामीण क्षेत्रों को अपना कार्यक्षेत्र भी नहीं बनाया। जयप्रकाश नारायण की प्रमुख हिस्सेदारी के बाद भी यह मध्यम वर्ग का शहरी आन्दोलन ही रहा। 1974 ई0 में जो आन्दोलन हुआ वह परिस्थितियों की उपज थी, परिस्थितियों यह थी कि लोग शासन से तो नाराज थे ही विरोधी दलों से भी लोगों का विश्वास टूट चुका था पहले की गैर कांग्रेसो सरकारों के कारण। इसलिए 1974 का आन्दोलन एक असंगठित शक्ति का ही रूप और परिणाम था। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने पटना

के गांधी मैदान में सम्पूर्ण क्रान्ति की घोषणा की थी।[2] सरकार का ध्यान खींचने के लिए तथा जनशक्ति को जागृत, चौकस तथा संगठित बनाये रखने के लिए 5 जून को सारे बिहार में सम्पूर्ण क्रांति दिवस मनायी गई। छात्र–संघर्ष समिति के 'सैकड़ों युवक 5 जून के दिन पटना में आपात तथा चुनाव के उपरान्त पहली बार संघर्ष समिति अधिकृत रूप से राजशक्ति तथा जनशक्ति के प्रति अपना दृष्टिकोण तथा आन्दोलन जारी रखी। 17–23 जनवरी 1977, दिनमान में प्रकाशित रविवार 3 अप्रैल 1974 ई0 का पटना का 'होटल प्रिंसेस' छात्र संघर्ष समिति का असामान्य प्रेस सम्मेलन में विजय कृष्ण ने छात्र नेताओं का परिचय देते हुए कहा कि शिवानंद तिवारी, नीतीश कुमार, अख्तर हुसैन, वशिष्ट नारायण सिंह, रामजतन सिन्हा, रघुपति आदि संघर्ष शील छात्र नेता उपस्थित थे। इसी दिन दिनमान में ही शिवानंद तिवारी का वक्तव्य आया कि दिल्ली में नयी राजशक्ति का उदय हुआ है, देश में विशाल जन शक्ति का सत्ता पलटी है, किन्तु व्यवस्था नहीं बदली है। व्यवस्था में आमूल तथा जनाभिमूख परिवर्त्तन महसूस की गई, परन्तु राजशक्ति तथा जनशक्ति में समन्वय भी जरूरी था। प्रशासन तंत्र पर जनशक्ति का अंकुश भी लगा रहे। इसलिए जे. पी. ने जन समिति बनाने का आह्वान किया था। छात्र संघर्ष समिति के लोग इस कार्यक्रम को तेजी से चला रहे थे। जन–समिति का संयमित तथा तीव्र परिवर्त्तन जरूरी समझा गया। इन जन समितियों का राज्य के साथ क्या संबंध होगा, गांव के विकास में इन समितियों की क्या भूमिका होगी, इन जन समितियों के माध्यम से जनता को भ्रष्ट प्रशासन तंत्र से छुटकारा कैसे दिलवाया जा सकेगा? देश तथा सरकार के सामने अनेक ज्वलंत प्रश्न थे। ये जन समितियाँ तीन स्तरों पर बनाई गई जिसके अन्तर्गत–पंचायत, प्रखण्ड तथा जिला स्तरों पर सरकारी प्रशासन तंत्र का सम्पूर्ण ढाँचा काम करती। पंचायत स्तर पर मुखिया, सरपंच, प्रखण्ड स्तर पर बी.डी.ओ., दारोगा तथा जिला स्तर पर एस.डी.ओ., जेलर, सिविल सर्जन, जिलाधिकारी आदि को रखा गया। इन समितियों की सिफारिश पर ही सरकारी पदाधिकारियों को पुरस्कार या दण्ड मिलने का प्रावधान बना। सभी अपने-अपने स्तर पर विकास की योजनाओं का आकलन करने लगी। जमीन पर लगने वाला कर इन समितियों का आर्थिक आधार निश्चित किया गया। जमीन पर 'करों' का एक हिस्सा पंचायत को, एक हिस्सा प्रखण्ड को तथा एक हिस्सा जिला समिति को तथा एक हिस्सा राज्य सरकार को दिये जाने की योजना बनी। राजशक्ति तथा जनशक्ति के समन्वय, जनचेतना का परिवर्त्तन तथा प्रगति के लिए उपयोग तथा नौकरशाही पर अंकुश लगाने की ठोस व्यवस्था बनाई गई। अचानक शिवानन्द तिवारी का वक्तव्य आया कि देश में अब गांवों पर आधारित योजनाएँ चलायी जायेगी, जिसमें खेती, उद्योग, कुटीर तथा लघु उद्योग, मध्यम तथा बड़ा उद्योग, शहरों द्वारा गांवों का शोषण तथा गांव की गरीबी तथा बेकारी हटानी होगी। इसके लिए जनता सरकार विभिन्न तरह की योजनाएँ हाथ में लेगी। सिंचित जमीन, 80 प्रतिशत खेती योग्य असिंचित है, किसानों को बिजलीदर कम लगे। इसके अलावे नहर रेट, खाद का मूल्य घटाया जाय, स्वच्छ पेय जल, आदि हर गांव में मिले। भूमि हीन, मजदूर दरिद्र, किसान, हरिजन आदिवासी को छोटे–छोटे उद्योगों के लिए सरकारी या अन्य स्त्रोंतों जैसे बैंक से बिना सूद कर्ज दिया जाये। इन तबकों को शीघ्र ऊपर उठाया जा सकता था।[6] छात्र संघर्ष समिति के नेताओं ने नक्सलवादी परिवर्त्तन की लड़ाई के लिए चार मांगे दिल्ली सरकार जनता पार्टी तथा लोकतांत्रिक कांग्रेस से की। प्रथम श्री जगजीवन राम तथा लोकतांत्रिक कांग्रेस के अन्य नेताओं से अनुरोध करना है कि वे जनता से किये गये अपने वायदे के अनुसार जनता पार्टी के साथ अपने दल का विलय कर ले। दूसरे, श्रीमती इन्दिरा गांधी के पूरे कार्यकाल की खुली जांच की जाये। तीसरे, दिल्ली सरकार से मांग करना है कि वह अविलम्ब विधान सभाओं का चुनाव कराये। चौथे, हिन्दुस्तान की जेल में बन्द करीब 35 हजार नक्सलवादी राजनैतिक कैदियों को अविलम्ब रिहा किया जाये। जयप्रकाश नारायण से नक्सलवादियों की वार्ता हो, इसका छात्र संघर्ष समिति के नेता स्वागत करेंगे।[3]

सन् 1973 ई. के दिसम्बर से ही जय प्रकाश नारायण देश में सम्पूर्ण क्रांति के लिए छात्रों की समस्याओं का अध्ययन कर युवकों एंव छात्रों का एक मोर्चा तैयार करने के लिए अभियान में लगे थे। शिक्षण संस्थाओं, होस्टल खर्चो की वृद्धि, परीक्षा सम्बन्धी अनियमितताएँ, परीक्षा फलों में मंत्रियों के हाथ, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में राजनीतिक का प्रवेश, छात्रों में बढ़ती जा रही असमानता; जातिवाद, बाहरी असामाजिक तत्वों का होस्टलों एवं कॉलेजों में प्रवेश आदि के कारण फैले छात्रों में असन्तोष और आक्रोश को संगठित रूप देकर देश की मूल समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष के लिए प्रेरित किया। बिहार के तत्तकालीन शिक्षा मंत्री श्री विधाकर कवि के पुत्र को अवैध रूप से ग्रेस मार्क देकर मगध विश्वविद्यालय के उप कुलपति ने उत्तीर्णता प्रदान करने से आरा के छात्रों को भो यही सुविधा प्रतिवर्ष देने की मांग कर रहे थे। छात्रों की मांगों पर ध्यान नहीं देने से भोजपुर के छात्रों ने हड़ताल किये, साथ ही बिहार राज्य के अन्य विश्वविद्यालयें को भी समर्थन और सहयोग देने की अपील की। जिसमें पटना, भागलपुर, बिहार, रांची विश्वविद्यालयों के छात्रों ने अपनी–अपनी समस्या तथा समाधान के लिए संघर्ष करते रहे थे। अक्टूबर 1974 ई0 में सम्पूर्ण क्रांति के दौरान पटना केन्द्रीय कारा में 'मीसा' के अन्तर्गत गिरफ्तार लेखक, छात्र नेताओं में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रमाकान्त ठाकुर, सुबोध कान्त सहाय आदि पमुख थे। जिन्होंने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ने 'तरूण शांति सेना' यूथ फोर डेमोक्रेसी विषय की बैठकों की अध्यक्षता लालू प्रसाद यादव ने किया और जे. पी. ने विषय को स्पष्ट किया। बैठक में दैनिक अंग्रेजी पत्र 'स्टेटसमैन' के सम्पादक श्रो कुलदीप नैयर ने भी छात्रों को सम्बोधित किया था। जयप्रकाश नारायण मुजफ्फरपुर, लंगटसिंह कॉलेज, राम दयाल सिंह कॉलेज के छात्रों को भी सम्बोधित किया जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं के रचनात्मक कार्यक्रम हेतु, अहिंसक संघर्ष करने की प्रेरणा दी। इन भाषणों का जोरदार असर बिहार के छात्रों पर पड़ा। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के छात्रों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य व्यापी छात्र–संगठन बनाने पर जोर दिया, और निर्णय लिया कि छात्र समुदाय किसी राजनीतिक फन्दे में न पड़े। इस तरह के आह्वान से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के छात्र–संघों कॉलेजों के तमाम विद्यार्थी संगठनों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन पटना विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन में हुआ जिसमें प्रदेश भर के 70 महाविद्यालयों से करीब 250 ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन पटना के हिन्दी दैनिक 'प्रदीप' के सम्पादक श्री राम सिंह भारतीय ने किया तथा मुख्य अतिथि पटना विश्वविद्यालय के उप कुलपति देवेन्द्र नाथ शर्मा भी उपस्थिति थे। छात्रों ने आन्दोलन के विधिवत संचालन के लिए 21 छात्रों की एक संचालन समिति गठित की गयी जिसके सदस्यों में प्रमुख थे– लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, जगन्नाथ प्र0 यादव, मिथिलेश कुमार सिंह, शिवानन्द तिवारी, नितीश कुमार, राम जतन सिंह इत्यादि इन्होंने अपने मांग पत्र से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा में आमूल–चूल परिवर्त्तन लाना चाहते थे। छात्रों ने पटना के अलावे राज्य के कई जगहों पर प्रदर्शन तथा जुलूस किये। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सीतामढ़ी, भोजपुर, रोहतास आदि जिलों में तो छात्रों ने जमाखोरी, मुनाफाखोरी के खिलाफ भी अभियान चलाया था। छात्रों ने मुख्यमंत्री श्री अब्दूल गफूर को ज्ञापन दिया और कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 18 मार्च 1974 से प्रारम्भ होने वाली विधान सभा का घेराव करेगे। राज्यपाल श्री आर.डी. भंडारे ने किसी भी

मंत्री, विधायक और अफसर को विधान सभा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। मुख्यमंत्री भी छात्रों की मांगों को नजर अंदाज कर दिया। यहाँ तक की 25 फरवरी से एक सप्ताह के लिए पटना में 144 धारा लागू कर दिया था और शिक्षक संस्थानों को भी बन्द कर दिया था। बिहार सरकार के इस मनमानेपन से लाचार होकर छात्रों ने 18 मार्च को विधान सभा के घेराव के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आन्दोलन में लग गये थे। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से भी 17 फरवरी 1974 को छात्र–युवकों ने बिहार राज्य छात्र सम्मेलन का बहिष्कार किया था। इतना ही नहीं उन्होंने 'बिहार राज्य छात्र–नौजवान मोर्चा के नाम से एक अलग संगठन बनाया था। ये बिहार प्रदेश छात्र–संघर्ष समिति की मांगों से मिलता जुलता मांग पत्र कार्यक्रम की रूप रेखा समानान्तर चला रहे थे। 16 मार्च को पूरे राज्य भर में जिलाधीशों के कार्यालय, शिक्षा मंत्री का घेराव, तोड़फोड़ हिंसात्मक कार्रवाईयाँ की थी। कइ जगह तो पुलिस ने गोलियाँ चलायी। बेतिया में तो सात लोग मारे भी गये थे और कई घायल भी हुए थे इसके साथ ही प्रदीप, सर्चलाइट, आर्यावर्त्त, इण्डियन नेशन और पी.टी. आई. के दफ्तरों को भी क्षतिग्रस्त की गयी थी, ये सारी घटनाएँ छात्रों के नाम पर हुई जो बिहार सरकार की दमनात्मक तैयारी के लिए औचित्य के तनाव का माहौल पैदा हुई थी। 23 मार्च 1974 को छात्रों द्वारा 'सम्पूर्ण बिहार बन्द' का आह्वान किया गया जिसमें अनेक छात्र गिरफ्तार कर लिये गये थे, फिर भी बन्द सफल रहा। 25 मार्च को छात्रों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व करने का आग्रह किया। जे.पी. ने छात्र नेताओं को आश्वासन दिया कि वे उनका नेतृत्व करेगें, मगर तीन शर्त्तो का पालन करना पड़ेगा – 1. संघर्ष शांतिपूर्ण होना चाहिए। 2. आन्दोलन एवं संघर्ष का नेतृत्व कोई राजनीतिक दल द्वारा न करें। 3. संघर्ष के लिए छात्रों को कम से कम एक वर्ष समय देना होगा। छात्रों ने जयप्रकाश नारायण के इन तीनों शर्त्तो को मान ली। 27 मार्च को दफा 144 की अवहेलना कर छात्रों ने गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन किया जिसमें जयप्रकाश नारायण अस्वस्थता के कारण नहीं आ सके तथा अनेकों छात्र नेता गिरफ्तार कर लिये गये थे। 30 मार्च को छात्रों के मौन जुलूस निकालने के प्रयास को भी सरकार ने विफल कर दिया। सरकार के इस रवैये से जयप्रकाश नारायण ने चेतावनी दी कि "वह विधार्थियों और लोगों से शांतिपूर्ण विरोध और कार्यवाही का उनका अधिकार न छीन अगर सरकार लोगों के शांतिपूर्ण आन्दोलन को इस तरह कुचलती रही तो हिंसक विस्फोट होकर रहेगा।[4] जयप्रकाश नारायण के वक्तव्य पर सरकारी क्षेत्रों में काफी प्रति क्रियाएँ हुई स्वयं प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी उड़ीसा में एक जन सभा में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जयप्रकाश नारायण निम्न स्तर की बातें की तथा बिहार आन्दोलन की आलोचना करते हुए कहा कि– "जो लोग अमीरों से पैसा लेते हैं उन्हें भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। समाचार पत्रों में श्रीमती गांधी के भाषण के प्रकाशित होते ही सारे दश में हलचल मच गयी प्रधानमंत्री का जवाब देते हुए जयप्रकाश नारायण ने कहा कि "प्रधानमंत्री ऐसे स्तर पर उतर रही है जहाँ मैं अपने को उतार नहीं सकता।[5]

8 अप्रैल 1974 को पटना के गलियों सड़कों मैदानों में प्रचण्ड गर्मी के मौसम में महिलायें बुढ़े, बच्चे, नवयुवक छा गये थे। लोगों ने अपनी मुंह पर पट्टी बांधकर और हाथ पीछे की ओर करते हुए अभूतपूर्व मौन जुलूस जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में निकाला। सरकार की तानाशाही के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस मौन जुलूस का असर सिर्फ बिहार पर ही नहीं पड़ा बल्कि सारे भारत पर भी पड़ा। भारत के प्रायः सभी प्रमुख अखबारों में इसकी चर्चा छपी। यहाँ तक कि बी.बी. सी. लन्दन ने इसे अभूतपूर्व मौन जुलूस कहा था। सरकार ठप करो एवं बिहार विधान सभा विघटन करो जैसे आन्दोलन छात्रों ने जयप्रकाश नारायण के समर्थन से शुरू किया। सम्पूर्ण क्रांति आह्वान कर जयप्रकाश नारायण ने छात्रों, जनता एवं युवा वर्ग की ओर से भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी एवं कुशिक्षा का प्रश्रय देने वाली सरकार के खिलाफ आन्दोलन का बिगुल फूँका। हर सरकारी कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन, अनशन, सत्याग्रह, मौन जुलूस, चौक चौराहें पर नुक्कड़ सभाएँ इत्यादि आन्दोलन के मुख्य रूप थे। इस आन्दोलन को दबाने के लिए सरकार ने दमानात्मक और शर्मनात्मक नीति अपनायी। 'मीसा' के अन्तर्गत छात्रों, शिक्षकों, वकीलों तथा जनता की गिरफ्तारी भी की थी। बिहार के विभिन्न जगहों पर शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन, अनशन कर रहे सत्याग्रही पर लाठी चार्ज, अश्रुगैस तथा विभिन्न तरह की यातनाएँ दी गयी। इस आंदोलन में भी कम्युनिस्ट पार्टी को भूमिका राष्ट्रीय आन्दोलन की तरह 'पीठ में छूरा भोंकने' जैसा रहा। यह आन्दोलन बाधाओं, रूकावटों तथा हिंसात्मक रूप लेकर बदनाम हो गया था। सरकार से साँठ–गाँठ कर आन्दोलन का विरोध किया तथापि आन्दोलन की गति को देखते हुए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार घबड़ा गयी और कांग्रेस का महासचिव चन्द्रशेखर को बिहार भेज कर तथा मंत्रियों से त्याग पत्र दिलवाकर 14 सदस्यीय मंत्रिमण्डल गठित की। कांग्रेस ने छात्र और जनता का मुंह बन्द करने के लिए 35 मंत्रियों को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हटवा दिया था। कांग्रेस सरकार से साँठ–गाँठ कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अभारतीय, अराष्ट्रीय दृष्टिकोण से कार्य किया तथा 3 जून 1974 ई. को ही कम्युनिस्ट छात्र आन्दोलन कर्त्ताओं ने दिखावा मात्र कर हस्ताक्षर एवं संग्रह–कार्य में शरीक हो गये थे।[6]

5 जून 1974 को ऐतिहासिक छात्र जन प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी। फिर भी ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गांधी मैदान में लाखों संख्या में छात्र–युवक, स्त्री–पुरूष, आन्दोलन में भाग लेने के लिए पटना पहुंचे। इस अभूतपूर्व जुलूस में लोगों ने पंक्तिबद्ध होकर अनुशासित एवं व्यवस्थित ढंग से हाथ में बैनर, पोस्टर, जिसमें भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्त्तन तथा "संगीनों में जोर कहां, जनशक्ति मजबूत जहां" 42 में भारत छोड़ो 74 में गद्दी छोड़ो" जैसे क्रांतिकारी नारों के साथ इन्दिरा गांधी की तानाशाही शासन की कुर्सी को डोला दिया था। आन्दोलन के दौरान कई जगह गोलियां भी चली फिर भी जुलूस शांतिपूर्वक अपने उद्देश्य तक आगे बढ़ता रहा था। 13 जुलाई 1974 ई. को हजारों छात्रों ने राजभवन के सामने प्रदर्शन कर राज्यपाल से मांग किया कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को एक वर्ष तक बन्द रखे, और परीक्षाओं को स्थगित कर शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया जाय। सरकार ने प्रचारात्मक तथा दमनात्मक कदम उठाते हुए कर्मचारियों को प्रलोभन देकर छात्रवेष में कक्षाओं में भेजना शुरू किया तथा बड़े पैमाने पर छात्रों की गिरफ्तारी की गयी थी। आन्दोलन में तीव्रता लाते हुए 'सरकार ठप करो' और करबन्दी अभियान' प्रारम्भ की, जिसमें राज्य के हर नगर प्रखण्ड शराब की भट्ठियों, अंग्रेजी शराब, सिनेमा घरों को बन्द करने तथा 9 अगस्त को सारे बिहार में 'सम्पूर्ण क्रांति दिवस' के रूप में मनाया गया। इस आन्दोलन के इतिहास में 15 अगस्त 1974 को राज्य भर में लोक स्वराज्य दिवस मनाया गया। 23 अगस्त 1974 ई. को पटना के गांधी मैदान में जे.पी. ने विशाल जनसमूह के बीच भाषण देते हुए घोषणा की, कि विधान सभा भंग कराये बिना आन्दोलन बन्द नहीं होगा। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, जमाखोरी जैसे ज्वलन्त समस्याएँ दूर करने की छात्रों ने जो मांग की है तो कोई गुनाह नहीं किया है। जयप्रकाश नारायण लखनऊ दौरा के क्रम में भारतीय क्रांति दल के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह से उत्तरप्रदेश में भी बिहार की तरह आन्दोलन छेड़ने के लिए विचार–विमर्श किया और लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के वार्षिक समारोह में उन्होंने छात्रों और युवकों को आह्वान किया कि देश में परिवर्तन लाने के लिए

संगठित होकर संघर्ष करे। जयप्रकाश नारायण लखनऊ दौरा खत्म कर पटना लौटे तो उनके इस दौरे का एक महत्वपूर्ण असर यह हुआ कि भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी, उत्कल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल, संसोपा, किसान मजदूर पार्टी, खेतिहर मजदूर पार्टी (पंजाब) इन सातों दलों ने अपना विलय कर एक नये दल 'भारतीय लोकदल' में कर दिया था, जिसके अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह बनाये गये थे।[7]

4 नवम्बर 1974 ई. को विधान सभा के समक्ष विशाल 'जन प्रदर्शन' किया। इससे बिहार के आम लोगों में उमंग की लहर दौड़ पड़ी। इधर सरकार भी इस जन प्रदर्शन को असफल बनाने की विभिन्न प्रकार की योजनाएँ बनाने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी भी सरकार के साथ सांठ–गांठ कर कार्य करने लगी। कांग्रेस आलाकमान श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बिहार आंदोलन को दबाने के लिए देवकान्त बरूआ को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। राज्य सरकार ने दमनात्मक कार्यवाई कर छात्रनेता जन संघर्ष नेता तथा विरोधी राजनैतिक नेता 'मीसा' (आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अध्यादेश (MISA—Maintenance of Internal Security Act) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दूसरे राज्यों के रहने वाले सर्वोदये नेताओं को भी बिहार राज्य से निष्कासित कर दिया था। सरकार की दमनात्मक कार्रवाई लाठी चार्ज, अश्रुगस, भीड़ पर पड़ने लगी, स्वयं जयप्रकाश, नानाजी देशमुख, श्यामनन्दन मिश्र, बाबू राव चन्दावार, आदि नेताओं को भी इसकी मार झेलनी पड़ी। ऐसी घटना से जे.पी. काफी मर्माहत हुए और जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर 5 नवम्बर और 6 नवम्बर को 'बिहार बन्द' कराया गया। बन्द बहुत सफल तथा शान्तिपूर्ण रहा था। श्रीमती गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल तथा कार्य समिति की बैठक में कहीं कि "बिहार का आन्दोलन सिर्फ मुझे सत्ता से हटाने के लिए है।" बिहार आन्दोलन से जनतंत्र को खतरा पैदा हो गयी थी। कांग्रेस इस चुनौती का डट कर मुकाबला करने को तैयार थी। प्रत्यान्दोलन की योजना के क्रम में कांग्रेस पटना में प्रदर्शन का आयोजन किया था। 4 दिसम्बर 1974 ई. को तनाव पूर्ण वातावरण में बिहार विधान मंडल का शीतकालीन सत्र प्रारम्भ हुआ था। छात्र–आन्दोलन के समर्थन में 319 विधायको में 38 विधायक पहले ही त्याग पत्र दे चुके थे। जनसंघ 24 में 13, संसोपा 17 में 10, सोपा 11 में 9, संगठन कांग्रेस 20 में 03, सत्ता कांग्रेस 178 में 01, श्री महामाया प्रसाद सिंहा, निर्दलीय 25 में 03, स्वतंत्र 01 सदस्यों के बाद में त्याग–पत्र दिये थे। विधानसभा बैठक के साथ प्रतिदिन घेराव, धरना, इत्यादि का कार्यक्रम चला था। इस समय लगभग दो हजार सत्याग्रहियों ने भाग लिया था जिसमें 936 ही जेल भेजे गये थे, बाकी को छोड़ दिया गया था।[8] पूरे देश भर में आन्दोलन को सशक्त बनाने के लिए संगठन, सभा, गोष्ठो की गयी थी, जे.पी. देश-व्यापी दौरा कर दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध थे। समग्र क्रांति के महान लक्ष्य को लेकर उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बंगाल, बिहार आदि प्रदेशों में सफलतापूर्वक सभाय, गोष्ठो संचालित करने में कामयाबी हासिल की थी। अखिल भारतीय छात्र संघ ने भी पूरे देश में आन्दोलन चलाने की गति प्रदान की थी। देशभर में समग्र क्रांति की आवाज–गूँजने लगी थी। बिहार आन्दोलन की मांग पूरे देश की मांग थी– "शिक्षा में आमूल–चूल परिवर्त्तन भ्रष्टाचार, मँहगाई, बेरोजगारी खत्म करने की"। पूरे देश में श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ जनमत जागृत होने लगी थी। जुलूस सभा-प्रदर्शन, अनशन, शुरू हो गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजनारायण बनाम श्रीमति इन्दिरा गांधी के मुकदमें का फैसला सुनाकर, अखिल भारतीय आन्दोलन की सुलगते आग में घी का काम कर दिया था।[9]

इस आंदोलन के अंत में आपातकाल की घोषणा हुई और जो बाद में 'जनता पार्टी' की जीत में तब्दील हुई तथा मार्च 1977 में केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी की छत्रछाया के तहत सभी गैर–कांग्रेसी दलों को एकत्रित करने का श्रेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण को ही जाता है।

संदर्भ

1. बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, दिनमान 22–28 जनवरी 1978 पृ. 33–34
2. श्री किशन पटनायक : दिनमान, 22–28 जनवरी 1978, पृ. 35
3. दिनमान, 17–23 जनवरी, 1977 पृ. 8, 9
4. राष्ट्रीय आन्दोलन और जयप्रकाश नारायण, लेखक डॉ. सुधारक लाल श्रीवास्तव, राधा पब्लिकेशन 4478/4 बी गली, मुरारी लाल अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन का प्रयोग क्षेत्र बिहार, पृ. 189–197.
5. सम्पूर्ण क्रांति के सूत्रधार–लोक नायक जय प्रकाश लेखक, अवध बिहारी लाल नवभारत प्रकाशन, खजांची रोड, पटना–4, पृ. 198, 199
6. पूर्वोक्त, पृ. 200, 203, 207, 208, 209, 213.
7. राष्ट्रीय आन्दोलन और जय प्रकाश नारायण लेखक डॉ. सुधाकर लाल श्रीवास्तव, राधा पब्लिकेशन्स 4478/4 बी. गली मुरारी लाल अन्सारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली, "सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन का प्रयोग क्षेत्र–बिहार, प्रथम संस्करण 1991, पृ. 214–217, 224, 225, 227–228.
8. सम्पूर्ण क्रांति के सूत्रधार– लोक नायक जय प्रकाश लेखक, अवध बिहारी लाल, नव भारत प्रकाशन, खजांची रोड, पटना 4, पृ. 239–244, 249, 261.
9. 1974 बिहार छात्र आन्दोलन एवं सम्पूर्ण क्रांति एक विश्वासधात, प्रकाशक–अरविन्द, लोकवाणी प्रिटिंग प्रेस, डी. एन. दास लेन लंगर टोली, पटना, पृ. 97.